

सऊदी अरब-ईरान राजनयिक संबंध बहाल करने हेतु सहमत

प्रलम्ब के लिये:

यमन में हूती वदिरोही, मध्य-पूरवी देशों की भौगोलिक स्थिति, पश्चिमि एशिया ।

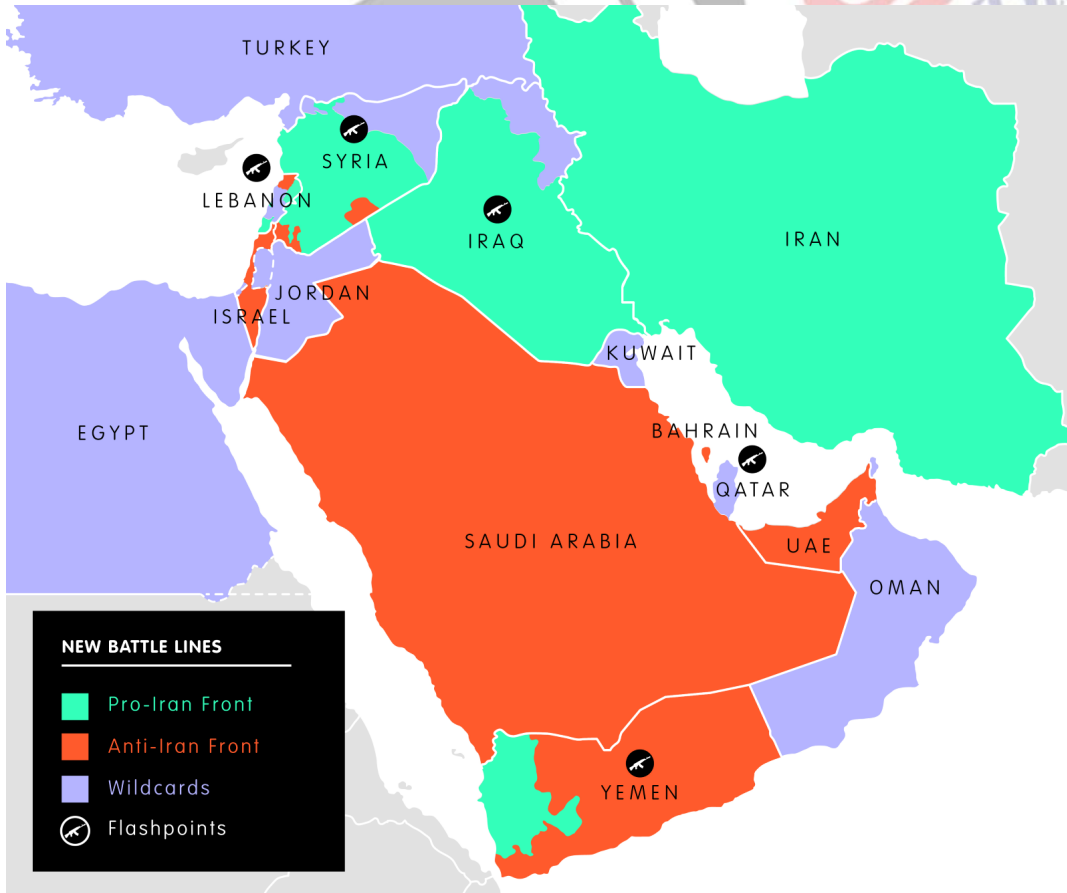
मेन्स के लिये:

सऊदी अरब-ईरान संबंधों में भारत की भूमिका, भारत के हतियों पर देशों की नीतियों और राजनीतिका प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के अधिकारियों ने द्वपिक्षीय वार्ता की जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016 से समाप्त राजनयिक संबंधों को बहाल करने हेतु एक समझौता हुआ । बीजिंग में चीन द्वारा महत्त्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धि हासिल की गई ।

- यह समझौता तब हुआ जब राजनयिक रूप से यमन में लंबे युद्ध को समाप्त करने की कोशिश हो रही है, एक ऐसा संघर्ष जिसमें ईरान और सऊदी अरब दोनों ही अत्यधिक उलझे हुए हैं ।



प्रमुख बदि

- ये दोनों देश तेहरान और रयाद में अपने-अपने दूतावास फरि से खोलने की योजना बना रहे हैं ।
- उन्होंने देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की भी शपथ ली ।
- वे वर्ष 2001 के सुरक्षा सहयोग समझौते के साथ-साथ वर्ष 1998 में हस्ताक्षरित एक सामान्य अर्थव्यवस्था, व्यापार और नविश समझौते को सक्रिय करने पर भी सहमत हुए ।

ईरान और सऊदी अरब के बीच वविाद:

■ धार्मिक कारक:

- सऊदी अरब में कुछ दनों पहले एक प्रमुख शया धरमगुरु की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों ने सऊदी राजनयिक चौकियों पर हमला किया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने वर्ष 2016 में ईरान के साथ संबंध समाप्त कर दिये थे ।
- सऊदी अरब ने लंबे समय से खुद को दुनिया के अग्रणी सुन्नी राष्ट्र के रूप में चित्रित किया है, जबकि ईरान ने खुद को इस्लाम के शया अल्पसंख्यक के रक्षक के रूप में प्रदर्शित किया है ।

■ सऊदी अरब पर हमले:

- ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने के बाद से ईरान को वर्ष 2019 में सऊदी अरब के तेल उद्योग को लक्षित करने सहित कई हमलों हेतु दोषी ठहराया गया था ।

- पश्चिमी देशों और वशिषज्जों ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया है, हालाँकि ईरान ने हमलों से इनकार किया है ।

■ क्षेत्रीय शीत युद्ध: सऊदी अरब और ईरान जैसे दो शक्तशाली पड़ोसी क्षेत्रीय प्रभुत्व हेतु संघर्षशील हैं ।

- अरब में विद्रोह (वर्ष 2011 के अरब सप्रगि के बाद) पूरे क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता का कारण बना है ।
- ईरान और सऊदी अरब ने अपने प्रभाव का वसितार करने हेतु इस अस्थिरता का फायदा वशिष रूप से सीरिया, बहरीन और यमन के संदर्भ में उठाया, जिसने आपसी संदेह को और बढ़ा दिया ।
- इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान के बीच संघर्ष को बढ़ाने में अमेरिका एवं इजरायल जैसी बाहरी शक्तियों की प्रमुख भूमिका है ।

■ परोक्ष युद्ध: ईरान और सऊदी अरब सीधे युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वे क्षेत्र के चारों ओर वभिन्न प्रकार से परोक्ष रूप से युद्धों (संघर्षों में जहाँ वे प्रतद्विपक्षी पक्षों और मलिशिया का समर्थन करते हैं) में रत हैं ।

- उदाहरण के लिये यमन में हूतविद्रोही । ये समूह अधिकि क्षमताएँ हासिल कर सकते हैं जो क्षेत्र में और अस्थिरता पैदा करेगा । सऊदी अरब ने ईरान पर उनका समर्थन करने का आरोप लगाया है ।

■ इस्लामी दुनिया का नेतृत्वकर्ता: ऐतहासिक रूप से सऊदी अरब एक राजशाही और इस्लाम का जन्मस्थान, खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में देखता था ।

- हालाँकि इसे 1979 में ईरान में हुई इस्लामी क्रांति ने चुनौती दी थी जिसने इस क्षेत्र में एक नए राज्य का नरिमाण किया, एक प्रकार का क्रांतिकारी लोकतंत्र- जिसका स्पष्ट लक्ष्य इस मॉडल को अपनी सीमाओं से परे पहुँचाना था ।

वैश्विक प्रभाव

- प्रतबिंधों के माध्यम से ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के अमेरिकी नेतृत्व के प्रयास इस सौदे के नहितार्थ हो सकते हैं क्योंकि यह सौदा ईरान के अंदर संभावित सऊदी नविश की सुविधा प्रदान कर सकता है ।
- यमन में सऊदी-ईरानी समर्थित हूतविद्रोहियों के खिलाफ आठ साल के गृहयुद्ध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ओमान हूतियों के साथ नजि वार्ता आयोजित करके युद्ध को समाप्त करने का रास्ता तलाश रहा है ।

- सऊदी अरब को यह उम्मीद है कि ईरान देश पर हूती ड्रोन और मसिाइल आक्रमणों को रोक देगा और ईरान हूतियों के साथ सऊदी वार्ता में मदद करेगा ।

- यह समझौता उन कई इजरायली राजनेताओं के बीच चिता पैदा करेगा जिन्होंने अपने कट्टर दुश्मन ईरान के लिये वैश्विक अलगाव की मांग की है । इजरायल ने समझौते को "गंभीर और खतरनाक" विकास के रूप में वर्णित किया ।

भारत पर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं?

■ ऊर्जा सुरक्षा:

- ईरान और सऊदी अरब वशिष के दो प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं और उनके बीच किसी भी तरह के संघर्ष से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है ।
- इन दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने से तेल की वैश्विक कीमतों को स्थिर करने और भारत को तेल की नरितर आपूर्ति

सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

■ **व्यापार:**

- ईरान और सऊदी अरब दोनों ही **भारत के महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हैं**। उनके बीच संबंधों को सामान्य बनाने से व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं, जिससे भारत के लिये आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी।

■ **क्षेत्रीय स्थिरता:**

- **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC)** सहित मध्य-पूर्व में भारत के मज़बूत आर्थिक और रणनीतिक हित हैं।
- ईरान भारत के **वसितारति पड़ोस** का हिस्सा है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता के भारत के लिये दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने से क्षेत्र अधिक स्थिर हो सकता है, जिससे संघर्ष एवं आतंकवाद के जोखिम को कम किया जा सकता है।

■ **भू-राजनीति:**

- **ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ** भारत का **सौहार्दपूर्ण संबंध है** तथा क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभाता है। इन दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने से क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों में मदद मिल सकती है।
- हालाँकि ईरान और सऊदी के बीच चीन की मध्यस्थता **भारत के लिये चुनौतियाँ पैदा करेगी क्योंकि यह क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ाने में योगदान करेगी**।

आगे की राह

- भारत इन दोनों देशों के मध्य संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता हासिल करने में मदद मिल सकती है।
- भारत को इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव से सतर्क रहने और मध्य पूर्व में अपने सामरिक हितों को सुरक्षित करने की दृष्टि में काम करने की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कसि दक्षिण-पश्चिमि एशियाई राष्ट्र की भू-सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? (2015)

- (a) सीरिया
- (b) जॉर्डन
- (c) लेबनान
- (d) इज़रायल

उत्तर : (b)

प्रश्न . नमिनलखिति में से कौन 'खाड़ी सहयोग परिषद' का सदस्य नहीं है? (2016)

- (a) ईरान
- (b) सऊदी अरब
- (c) ओमान
- (d) कुवैत

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का क्या महत्त्व है? (2017)

- (a) अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- (b) ऊर्जा का उत्पादन करने वाले अरब देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार होगा।
- (c) अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच के लिये भारत पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा।
- (d) पाकिस्तान, भारत और इराक को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन के निर्माण में सहायता और सुरक्षा करेगा।

उत्तर : (c)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

